

NT>

Title: Need to accord status of Scheduled Caste to Bangladeshi immigrants, settled in India and belonging to the Namasudra and Pundra Kshatria communities.

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): Mr. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of this House to the negligence of the Government towards the sad plight of several lakhs of settlers from the then East Pakistan – now Bangla Desh – who were uprooted from their soils in the 50s and 60s and settled in several districts like Udham Singh Nagar and all that.

12.49 hrs. (Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

Under the Government of India Act, 1935, they were recognised as Scheduled Castes. The Schedule mentioned that. But they have been denied that status for the last 40-50 years on account of official apathy and prevarication. They belonged, by and large, to the Namasudra and Pundra Kshatria communities. These are all recognised as Scheduled Castes as per the Schedule attached to the Government of India Act, 1935. But when they came here and were settled by the Government of India, they cut down the forests and reclaimed them. They turned those lands into cultivable ones and grew rich crops there. But they have been systematically denied the status of Scheduled Castes for the last nearly 40-50 years. This is a very serious matter. They have been denied educational and employment opportunities. The successive Governments in Uttar Pradesh gave them promises but have not done anything for them.

After a long time, the Government of Uttaranchal is now believed to have recommended their case to the Union Ministry of Home Affairs. I appeal to the Union Minister of Home Affairs to give them this long delayed justice so that they can restart their lives with dignity.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं भी बोलना चाहता हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will allow you to associate with him.

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, आजादी के 54-55 वर्षों के बाद भी शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को एक राज्य में शैड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी में रखा जाता है जबकि दूसरे राज्यों में उन्हें शैड्यूल्ड कास्ट नहीं माना जाता है। हम जानते हैं कि हर राज्य के अपने-अपने नियम बने हुए हैं। शैड्यूल्ड कास्ट के लोग जिस स्टेट में पैदा होते हैं उन्हें वहां तो शैड्यूल्ड कास्ट माना जाता है लेकिन अन्य राज्यों में नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को भी।

श्री राम विलास पासवान : जी सर, थैंक्यू सर। जैसे पासवान हैं वे बिहार में शैड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी में हैं लेकिन दिल्ली में नहीं हैं। फिशरमैन पश्चिम बंगाल में शैड्यूल्ड कास्ट में हैं लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में बैकवर्ड-क्लास में हैं। धोबी हैं, वे यहां तो शैड्यूल्ड कास्ट में हैं लेकिन कर्नाटक तथा अन्य राज्यों में इस श्रेणी में नहीं हैं। अगर शैड्यूल्ड कास्ट का आदमी किसी दूसरे राज्य में चला जाता है तो उसका स्टेट्स कोई बढ़ नहीं जाता है, वह शैड्यूल्ड कास्ट ही रहता है। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इस पर एक चर्चा होनी चाहिए कि अगर कोई शैड्यूल्ड कास्ट का आदमी किसी दूसरे राज्य में जा तो उसे शैड्यूल्ड कास्ट ही माना जाए। सरकार कह सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवा में उसे मान्यता है, लेकिन मेरा कहना है कि जब वह किसी दूसरे राज्य में जाता है तो उस राज्य की सेवा के लिए उसे कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इसलिए हमारी मांग है कि शैड्यूल्ड कास्ट या शैड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी देश के किसी भी कोने में जाए, उसे उसी श्रेणी में मान्यता दी जानी चाहिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष जी, नुनिया, मल्लाह, तत्मा, कुम्हार, तुरहा जातियों को कुछ राज्यों में तो शैड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी में मान्यता है लेकिन कुछ राज्यों में उन्हें बैकवर्ड क्लास में रखा जाता है। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

SHRI VINAY KUMAR SORAKE (UDUPI): Sir, we should have a half-an-hour discussion on this...(Interruptions)

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Sir, so many people from Tamil Nadu, especially SC/ST people, have come to Delhi but they could not get any benefit. My request is that they should be included in the SC/ST list so that they can get the benefits, like medical facilities, education, etc. here too...(Interruptions)